दैनिक
उत्तराखण्ड प्रहरी

वर्ष 15 /अंक 50 / पृष्ठ 8
हरिद्वार, बुधवार, 19 अप्रैल 2023
uttarakhandprahari19@gmail.com / e-paper: uttarakhandprahari.com
उत्तराखण्ड का सबसे विश्वसनीय मीडिया पार्टनर
RNI No. : - UTTHIN/2009/27592

डॉलर की सत्ता से मुक्ति का मार्ग | राज्य में युवाओं को अब इस काम से संबंधित दिया | मूल्य- 2 रु.

समलैंगिक विवाह पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा- हम सब कुछ नहीं तय कर सकते

नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिये जाने की मांग पर शुरू हुई चर्चा के बीच सरकार और जमीयत उलमा ए हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने कई आशंका तो जता दी है लेकिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान अहम है। उन्होंने सिर्फ सीमित मुद्दों पर सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि भविष्य की पीढ़ियों को बांध कर नहीं रखा जा सकता है। मंगलवार को याचिकाकर्ताओं ने संविधान मे मिले बराबरी के मौलिक अधिकार की दुहाई देते हुए कहा कि उन्हें भी विपरीत लिंगीयों के समान समझा जाए और विपरीत लिंगियों की तरह समलैंगिकों की शादी को भी कानूनी मान्यता दी जाए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विवाह करना हमारा मौलिक अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के कई फैसलों में कह चुका है कि सभी को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है। रोहतगी ने कहा कि उनकी मांग है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए और उनकी शादी पंजीकृत हो। कोर्ट ने आइपीसी की धारा 377 के आपराधिक भाग को खत्म कर दिया था अब बात बराबरी की है। उनकी दलीलों पर पीठ ने कहा कि कोर्ट को इस मामले में कानून के विधायी पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। इस मामले में कानून न होने पर कोर्ट किस हद तक

आदेश दे सकता है। रोहतगी ने कहा कि विशाखा जजमेंट की तरह कोर्ट गाइडलाइन जारी करे और कानून बनने तक वह लागू रहे। संसद के कानून बनाने का इंतजार नहीं किया जा सकता और कोर्ट भी संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता।

यह जटिल मुद्दा है

सालिसिटर जनरल ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में पुरुष और स्त्री की बात की गई है। सामाजिक संबंधों की स्वीकृति कभी भी कानून से नहीं आती ये अंदर से आती है। सीजेआइ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में पुरुष और स्त्री की अवधारणा सिर्फ जननांग पर आधारित नहीं है। यहां सवाल यह नहीं है कि जननांग क्या है यह ज्यादा जटिल मुद्दा है। मेहता ने कहा कि कोर्ट कह रहा है कि वह पर्सनल ला पर विचार नहीं करेगा ऐसे ही पिछले फैसले में कोर्ट ने कहा था कि वह विवाह की मान्यता के मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा लेकिन उससे विंडो तो खुल गई। और अब दोबारा वैसी ही विंडो खुल जाएगी। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी जो कि एक राज्य सरकार की ओर से पेश हुए थे, ने मेहता की दलीलों का समर्थन करते हुए राज्यों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुने जाने की मांग की। राकेश द्विवेदी ने याचिका में की गई मांगों का विरोध करते हुए कहा कि पहले यह तय होना चाहिए कि क्या इस मामले में समलैंगिक लोगों को

आज बहस जारी रहेगी

कोर्ट को पूरे मामले पर हर पहलू से विचार करना होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से शादी से जुड़े बच्चा गोद लेने के अधिकार के अलावा बैंक में खाता खुलवाने, बीमा में साथी को नामिनी बनाने और घर किराए पर लेने आदि के दौरान आने वाली दिक्कतें गिनाई गईं जिस पर सालिसिटर जनरल ने ट्रांसजेंडर एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून में इस तरह के सारे अधिकारों को संरक्षित किया गया है इसकी परिभाषा व्यापक है।

विपरीत लिंगीय लोगों के बराबर माना जा सकता है। नवतेज के फैसले में कोर्ट ने उन्हें बराबर नहीं माना है सिर्फ उस धारा का आपराधिक चरित्र खत्म किया है। जमीयत उलेमा हिन्द की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका मानना है कि लोगों को निजी स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन अगर समलैंगिग शादी को मान्यता दी जाती है तो आगे के परिणामों पर भी विचार होना चाहिए। अगर वह शादी टूटती है तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा।

वैश्विक स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी: मांडविया

नयी दिल्ली (वार्ता) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर देते हुए मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी - पश्चात - प्रभाव को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मांडविया ने आज गोवा में जी-20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर घबराहट और उपेक्षा के भाव समाप्त के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए कोरोना महामारी के बाद के प्रभाव को खत्म करने के प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। महामारी के फैलाव को रोकने तथा नियंत्रित करने के प्रयास लगातार जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा , 'जी- 20 स्वास्थ्य कार्य समूह कार्य के रूप में, हम संयुक्त रूप से भविष्य के वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की दिशा में सही दिशा में बढ़ रहे हैं।'

गंगा आरती देख निहाल हुए जी20 के डेलीगेट्स, शंखनाद से हुआ स्वागत, लोकनृत्य पर जमकर थिरके

वाराणसी । जी-20 सम्मेलन के मेहमानों ने गंगा की अलौकिक आरती देखी। इससे पहले नमो घाट पर उनका परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। नृत्य कर रहे कलाकारों के साथ मेहमान भी थिरकने लगे। इसके बाद वह क्रूज पर सवार होकर दशाश्मवेध घाट पहुंचे। आरती के दौरान मेहमानों के लिए विशेष शंखनाद हुआ।

बता दें कि 17 अप्रैल से वाराणसी में जी20 का आगाज हो गया है। भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि के विकास का नया रोडमैप वाराणसी में तैयार होगा। 19 अप्रैल तक चलने वाले जी-20 सम्मेलन में कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर सभी देशों के कृषि वैज्ञानिक मंथन करेंगे। नदेसर स्थित तारांकित होटल में 17 अप्रैल को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि काशी से दुनिया भर में एक अभियान शुरू किया जा रहा है। मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी से विश्व को उनके खान-पान से स्वस्थ रखने का संदेश दिया जाएगा। भारत सरकार वाराणसी से पोषण, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रख रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ हिमांशु पाठक व सचिव संजय ने बताया कि सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन व वैश्विक व्यापार संगठन सहित कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली कई संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं।

सीएम योगी का निर्देश, राज्य पशु 'बारहसिंघा' और राज्य पक्षी 'सारस' के संरक्षण के लिए बनाएं कार्ययोजना

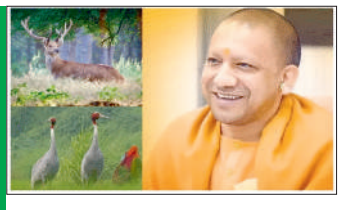

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 14वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की जैव विविधता को संरक्षित करने और इको पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कुकरैल नाइट सफारी, लखनऊ और रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस संबंध में वन्य जीव विभाग, नगर विकास, पीडब्ल्यूडी और आवास विभाग मिलकर अच्छी कार्ययोजना तैयार करें। यह दोनों परियोजनाएं प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा और जैव विविधता को नई पहचान देने वाली होंगी। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह दोनों नवीन स्थल एक उपहार होंगे। इस संबंध में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए। नियोजित प्रयासों से प्रदेश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2014 में कुल 117 बाघ प्रदेश में थे जो 2018 में बढ़कर 173 हो गए हैं। विगत दिनों जारी रिपोर्ट में शिवालिक एंड गंगा प्लेन लैंडस्केप में 804 बाघों के होने की पुष्टि हुई है। यह सुखद संकेत है। जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में हमें अपने प्रयास सतत जारी रखना चाहिए।

नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती:सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को कहा कि आप (गुजरात सरकार) सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते, उसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा कि जब विचाराधीन अपराध ₹जघन्य₹ और ₹भयानक₹ था तो राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह दिमाग का इस्तेमाल करे।

आवश्यक सूचना

'उत्तराखंड प्रहरी' के सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि आप अपने प्रिय अखबार 'उत्तराखंड प्रहरी' महाभियान में शामिल हो सकते हैं। आप अपने द्वारा लिखी गई कोई भी संरचना, कविता, कहानी, लेख या कार्यक्रम हमसे साझा कर सकते हैं। अच्छे लेख व कहानी को 'उत्तराखंड प्रहरी' में उचित स्थान दिया जाएगा। आप अपने प्रियजनों को जन्मदिन, सालगिरह या अन्य शुभ अवसरों पर बधाई संदेश भी दे सकते हैं।

आप हमें ईमेल
uttarakhandprahari19@gmail.com या whatsup no 8077771906 पर भी भेज सकते हैं।

संपादकीय

सीबीआई के घेरे में केजरीवाल

सीबीआई के सवालों का सामना करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने कहा कि बीते साल 17 सितंबर को शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने 1000 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने आरोप को बार-बार दोहराया। फिर सवाल किया कि यदि बिना साक्ष्य के ऐसे आरोप लगाए जाएं, तो उनके क्या मायने हैं? केजरीवाल ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सरीखी स्वायत्त और संवैधानिक जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल किए और कहा कि ऐसे ही बेमानी और बेबुनियादी आरोपों के आधार पर विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसा जा रहा है। अनर्गल आरोपों के सिलसिले इस कदर जारी रहते हैं कि अदालतें आसानी से जमानतें भी नहीं दे पा रही हैं। केजरीवाल के ऐसे आरोप और ऐसी अवधारणा हास्यास्पद हैं। ये जांच एजेंसियां हमारी व्यवस्था का अंतिम चरण हैं। जब भी कोई घोटाला फूटता है या काले पैसे के पहाड़ जब्त किए जाते हैं अथवा भ्रष्टाचार का कोई गंभीर मामला सामने आता है, तो राज्य सरकारें या प्रभावित-पीड़ित पक्ष सीबीआई जांच की मांग करते रहे हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और कथित शराब घोटाले के संदर्भ में सीबीआई ने केजरीवाल से करीब 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 56 सवाल किए।

केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने सभी सवालों के माकूल जवाब दिए। मुख्यमंत्री होने के नाते कैबिनेट की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, वह उसके 'प्रथम पुरुष' हैं। सरकार की नई आबकारी नीति बनी, फिर पुरानी नीति पर ही लौटना पड़ा, नीति के तहत शराब के थोक ठेकेदारों को जो फायदे, मुनाफे दिए गए, कथित घूस के आरोप लगे, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल उन प्रकरणों से तटस्थ नहीं रह सकते। बेशक उन्होंने किसी फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए अथवा नहीं किए, कैबिनेट के फैसले की पहली जिम्मेदारी उनकी है, लिहाजा उन्हें सवालों के कटघरे में आना ही पड़ेगा। केजरीवाल का आरोप है कि यह जांच ही 'फर्जी' है, क्योंकि सीबीआई के पास 'सबूत का एक टुकड़ा' तक नहीं है। इस निष्कर्ष पर केजरीवाल कैसे पहुंच गए? यह तो अदालत का विशेषाधिकार है। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं, सांसदों और मंत्रियों को हमारी नेक सलाह है कि वे यह जुमला उछालना बंद कर दें कि वे 'कट्टर ईमानदार' हैं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। हमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि 'आप' देश की नई राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रही है। दरअसल यह छवि देश की आम जनता और अंततः अदालत ही तय करेंगी। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और कुछ मित्रगण और शराब-ठेकेदार फिलहाल जेल में हैं। उन्होंने पूछताछ के दौरान सीबीआई और ईडी को कुछ तो खुलासे किए होंगे। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं। अब उनका मिलान मौजूदा साक्ष्यों से किया जाएगा और उसी के बाद एजेंसी बयान को सत्यापित करेगी। केजरीवाल सीबीआई जांच से मुक्त नहीं हुए हैं। हम किसी के भी आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। इसे जांच एजेंसियों और अदालत के विवेक पर छोड़ते हैं। भ्रष्टाचार और बेईमानी का उदाहरण तो उनके स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येन्द्र जैन हैं, जो करीब 11 महीने से जेल में हैं और अदालत उन्हें किसी भी आधार पर जमानत देने को तैयार नहीं है। केजरीवाल को कई स्तरों पर खुद को साबित करना होगा।

डॉलर की सत्ता से मुक्ति का मार्ग

डा. अश्विनी महाजन

पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक हमने डॉलर की मजबूती देखी है। पहले विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों ने संयुक्त राज्य अमरीका को आपूर्ति के बदले सोना देना शुरू किया, जिसके बलबूते अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार बन गया। युद्ध खत्म होने के बाद विभिन्न देशों ने अपनी कैरेंसियों को डॉलर के साथ जोड़ दिया और इसके साथ ही दुनिया में 'गोल्ड स्टैण्डर्ड' का अंत हो गया और साथ ही साथ डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा पसंदीदा कैरेंसी बन गई। सभी मुल्क अपने विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा से ज्यादा डॉलर के रूप में रखने लगे। 1999 तक दुनिया के मुल्कों के कुल विदेशी मुद्रा भंडार 70 प्रतिशत तक डॉलर में रखे जाने लगे। 1999 में यूरोपीय साझा कैरेंसी यूरो का उदय हुआ और कुछ यूरोपीय देशों को छोड़कर शेष सभी ने देर-सबेर अपनी कैरेंसी के बदले यूरो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका असर डॉलर पर भी पड़ा और कुछ यूरोपीय कैरेंसियों और डॉलर के बदले अब यूरो विदेशी मुद्रा भंडारों के लिए पसंद किया जाने लगा और विदेशी मुद्रा भंडारों में वर्ष 2021 के प्रारंभ तक आते-आते डॉलर का हिस्सा मात्र 59 प्रतिशत ही रह गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से यह हिस्सा और कम होकर वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही तक मात्र 55 प्रतिशत ही रह गया।

दुनिया भर में अब डॉलर के प्रति आसक्ति कम होती दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि डॉलर अभी भी किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि कुछ कैरेंसियों को छोड़कर दुनिया की लगभग समस्त कैरेंसियों की तुलना में डॉलर साल दर साल मजबूत और अधिक मजबूत होता रहा है। इंग्लैंड के पाउंड की तुलना में देखें तो जहां आज एक अमरीकी डॉलर 0.81 ब्रिटिश पाउंड के बराबर है, वहीं वर्ष 2014 में यह औसतन 0.59 ब्रिटिश पाउंड के बराबर था। दूसरी कैरेंसियों की हालत भी लगभग इसी प्रकार रही। एक अमरीकी डॉलर जो वर्ष 2014 में 0.75 यूरो के बराबर था, आज वह 0.93 यूरो के बराबर पहुंच चुका है। आज एक अमरीकी डॉलर 131.51 जापानी येन के बराबर है, यही 2014 में औसतन 121 जापानी येन के बराबर था। इतिहास में डॉलर के प्रति दुनियाभर के मुल्कों की आसक्ति के कारण डॉलर दुनिया की अन्य कैरेंसियों, खासतौर पर विकासशील देशों की कैरेंसियों की तुलना में लगातार मजबूत होता गया। जहां 1980 में एक डॉलर मात्र 7.86 भारतीय रुपए के बराबर था और आज यह 82.20 रुपए तक पहुंच चुका है।

कई अन्य मुल्कों की कैरेंसियों के मुकाबले तो यह और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। शायद इसीलिए दुनिया के तमाम मुल्क डॉलर को ही रिजर्व कैरेंसी रखने और अपने सभी अंतरराष्ट्रीय भुगतान डॉलरों में ही करने में रुचि रखते रहे हैं। डॉलर की इसी बढ़ती मांग के चलते डॉलर और अधिक मजबूत होता गया। लेकिन पिछले कुछ समय से रिजर्व कैरेंसी के नाते डॉलर की मांग कम होती जा रही है। जानकार लोग इस प्रवृत्ति को डी-डॉलरीकरण का नाम दे रहे हैं। जैसे पूर्व में पूरी दुनिया का डॉलरीकरण हुआ, लेकिन अब दुनिया में डी-डॉलरीकरण हो रहा है। समझने की आवश्यकता है कि जहां अमरीकी डॉलर इतिहास में सबसे अधिक मजबूत स्थिति में है, तो भी दुनिया में रिजर्व कैरेंसी के नाते डॉलर के प्रति आसक्ति क्यों कम हो रही है। यदि विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण फरवरी 2022 से चल रहा रूस-यूक्रेन युद्ध है। संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों का कहना है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया है, इसलिए दुनिया के सभी देशों को रूस से संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए।

अमरीका ने न केवल रूस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि वैश्विक भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से उसको बेदखल कर दिया है। माना जा रहा है कि भुगतान प्रणाली पर अमरीका और यूरोपीय देशों के दबदबे के चलते रूस के डॉलरों में विदेशी मुद्रा भंडारों की निकासी नहीं हो सकती। यानी रूस को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा भुगतान प्रणाली को युद्ध के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में स्वभाविक तौर पर रूस और उसके मित्र देश अब किसी भी हालत में अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को डॉलरों में रखने के लिए तैयार नहीं। अमरीका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के चलते दुनिया के मुल्कों पर यह भी दबाव बनाया जा रहा है कि वे रूस से कच्चा तेल न खरीदें। रूस अपने ऊपर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचने को तैयार है।

नई शिक्षा नीति और व्यावसायिक शिक्षा

डा. पंकज शर्मा

न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में दिए जाने वाली शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। भारतीय शिक्षा नीति में पिछले 3 दशकों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य भारत में दी जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार देखा जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिद्धांत कहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता दूसरे से अलग है। उसकी क्षमता को पहचान कर विद्यार्थी का संपूर्ण विकास होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोडना, सुशासन सिखाना, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान देना तथा बच्चों की सोच को रचनात्मक और तार्किक बनाना इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। यह कहना भी उचित होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई क्रांतिकारी सुधार हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने 18 सितंबर 2020 को मंजूरी मिलते ही तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। नई नीति के तहत जमा 1 से स्नातक तक विज्ञान, वाणिज्य तथा कला संकाय नहीं होगा। विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार विज्ञान, गणित, आईटी और वोकेशनल विषयों को पढ़ेगा। आईटी और वोकेशनल विषय विद्यार्थी छठी कक्षा से ही पढना शुरू कर दें, इसका भी प्रावधान किया जा रहा है।

संस्कृत विषय को तीसरी कक्षा से ही पढ़ाया जाएगा। स्नातक में डिग्री सिस्टम को खत्म करके क्रेडिट स्कोर सिस्टम लागू किया जाएगा, जहां 4 वर्ष की डिग्री का विकल्प होगा। 4 वर्ष की डिग्री के बाद पीजी केवल 1 वर्ष की होगी। एमफिल को पहले ही खत्म कर दिया गया है जबकि पीएचडी के लिए पूरे देश में एक ही टेस्ट होगा। नई नीति में हिमाचल प्रदेश में 10वीं और जमा 2 में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दो बार परीक्षा लेने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि विद्यार्थियों में तनाव खत्म किया जा सके। नई शिक्षा नीति को रोजगार से सीधा जोड़ा गया है, जिससे विद्यार्थियों को क्षमता के आधार पर रोजगार के अवसर मिल सकें। नई शिक्षा नीति में रोजगार चाहने वालों के स्थान पर रोजगार प्रदान करने वालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों को रटने की आदत से समीक्षात्मक सोच की ओर अग्रसर करेगी। हमारे देश में वोकेशनल स्टडी सीखने वाले छात्र 5 फीसदी से भी कम हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को वोकेशनल स्टडीज सीखने पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें बागबानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम आदि शामिल हैं। 2025 के अंत तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम 50 फीसदी छात्रों को वोकेशनल स्टडीज पढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेशभर के 54 नए स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स की कक्षाएं शुरू होंगी। इन सभी स्कूलों में नौवीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषय पढ़ाए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश के 1100 स्कूलों में 15 विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक कोर्स संचालित हैं। इन स्कूलों में 91277 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा से जोडने के लिए स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स को विशेष रूप से संचालित किया जा रहा है।

जिससे विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस नीति का उद्देश्य छात्रों के पाठ्यक्रम भार को कम करना और उन्हें 'बहुभाषी' बनाने की अनुमति देना है। 'यदि कोई छात्र भौतिकी के साथ फैशन की पढ़ाई करना चाहता है, या यदि कोई रसायन विज्ञान के साथ बेकरी सीखना चाहता है, तो वे ऐसा करने की अनुमति देंगे'। रिपोर्ट कार्ड 'समग्र' होंगे, जो छात्र के कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम न मान कर पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा जिसमें योग, खेल, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत आदि शामिल हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा जिससे कि छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिले।

वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश के 12 महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए बी-वॉक के तहत हॉस्पिटैलिटी तथा टूरिज्म और रिटेल मैनेजमेंट कोर्स प्रारंभ किए गए थे। इसके सफलतापूर्ण चलने के उपरांत छह और राजकीय महाविद्यालयों में यही कोर्स प्रारंभ किया गया और अब वर्तमान में 18 राजकीय महाविद्यालयों में यह कोर्स उच्च शिक्षा विभाग के तहत चलाया जा रहा है, जिससे 75 फीसदी के करीब प्रशिक्षु पढने के बाद नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।

वैधानिक सूचना

उत्तराखंड प्रहरी के संपादन में हम प्रयासरत है कि हमारी ओर से खबर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। हमारी कोशिश है कि अखबार में छपी किसी खबर, रिपोर्ट, फीचर या लेख से व्यक्ति विशेष, संगठन या समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचे। **उत्तराखंड प्रहरी** में प्रकाशित लेख, विश्लेषण और साभार, ली गई सामग्री के विचार संबंधित लेखकों और रचनाकारों के निजी विचार हैं, न कि अखबार के। अतः सभी पाठकों से आग्रह है कि वे किसी सूचना, समाचार, विज्ञापनों आदि के आधार पर कोई फैसला करने से पहले तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। उसके लिए किसी भी प्रकार से लेखक, संपादक, प्रकाशक, प्रिंटर या विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तथा किसी भी कारोबारी और निज निर्णय के लिए **उत्तराखंड प्रहरी** जिम्मेवार नहीं होगा।

राज्य में युवाओं को अब इस काम से संबंधित दिया जायेगा प्रशिक्षण : मुख्यमंत्री धामी

राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं : मुख्यमंत्री धामी

बेहतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भी स्विस एजुकेशन ग्रुप से मदद ली जाएगी : धामी

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्लाडियो रैकनेलो के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने भेंट की। इस अवसर पर राज्य में युवाओं को पर्यटन एवं होटल व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में यहां के युवाओं में स्किल को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को पर्यटन एवं होटल व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए, यदि स्विटजरलैण्ड से कुछ अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो सकती है, तो इस दिशा में कार्य किया जाए। राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जायेगी। युवाओं को सर्टिफिकेट कोर्स की अच्छी सुविधा मिलने से उनके हुनर को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत राज्य में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बेहतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भी स्विस एजुकेशन ग्रुप से मदद ली जाए। विद्यार्थियों को बेहतर व्यावसायिक शिक्षा मिले इसके लिए विस्तृत योजना बनाई जाए। राज्य में पर्यटन के साथ-साथ साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन, शिक्षा, साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्विटजरलैण्ड से यदि कोई प्रतिनिधिमण्डल आना चाहता है, तो उनको देवभूमि उत्तराखण्ड में सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जायेगा। स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री क्लाडियो रैकनेलो ने कहा कि स्विट्जरलैंड में आध्यात्मिक गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य करने की काफी संभावनाएं हैं। यदि वहां पर आध्यात्मिक गतिविधियों पर आधारित केन्द्रों में उत्तराखण्ड से इस क्षेत्र के विशेषज्ञ कार्य करें, तो इसमें कार्य करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की ओर से जो भी सहयोग मांगा जायेगा, उसे पूरा करने के हर संभव प्रयास किये जाएंगे। इस अवसर पर स्वामी अभय दास, सूर्य प्रताप सिंह, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

महाराजा अग्रसेन के जीवन बारे में जान सके आने वाली पीढ़ी: राकेश गोयल

महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि हरियाणा रवाना हुई अग्रसेन वैश्य समाज के लोग

वैश्य समाज के सैकड़ों लोगों को बस से निशुल्क ले जाया गया हरियाणा

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। महाराजा अग्रसेन वैश्य समाज हरिद्वार के अध्यक्ष राकेश गोयल के नेतृत्व में समाज के सैकड़ों लोग महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि अग्रोहा धाम हिसार हरियाणा के लिए रवाना हुए है। पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने मायापुर स्थित सेफ पार्किंग से बस को हरी झंडी दिखाकर हरियाणा के लिए रवाना किया।

पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन हमारे पूर्वज हैं और गौरव, आन बान शान हैं। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन वैश्य समाज द्वारा अग्रोहा धाम की यात्रा शुरू करना सराहनीय कार्य है। इससे आने वाली पीढ़ी को महाराजा अग्रसेन के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा।

महाराजा अग्रसेन वैश्य समाज हरिद्वार के अध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि पहली बार हरिद्वार से वैसे समाज के लोग महाराज अग्रसेन की कर्मभूमि के लिए यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह यात्रा उनकी ओर से समाज के लोगों को निशुल्क कराई जा रही है। एयर कंडीशनर बस के जरिए समाज के सैकड़ों लोगों को यात्रा कराई जा रही है। पूरी व्यवस्था निशुल्क रहेगी। महामंत्री राजकुमार गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन वैश्य समाज सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता चला आ रहा है। समाज के लोगों को संगठित करते हुए एक मंच पर लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरतमंदों को समान वितरित करने से लेकर रक्तदान शिविर, चिकित्सा जांच शिविर, गरीब कन्याओं के विवाह सहित तमाम सामाजिक कार्य बढ़ चढ़कर किए जायेंगे।

अरविंद बबली, राजकुमार गुप्ता ₹भोला₹ राघव मित्तल, तेज प्रकाश साहू, आशुतोष मित्तल, अरुण अग्रवाल, कमल बृजवासी, राजकुमार गुप्ता बिंदी वाले, विजय अग्रवाल, गिरीश अग्रवाल, आदि मौजूद रहे।

नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई 200 एमएल शराब टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक, कहा- इससे पर्यावरण को होगा नुकसान

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

नैनीताल। हाई कोर्ट ने आबकारी नीति-2023 की धारा-5.5 के अंतर्गत 200 एमएल शराब टेट्रा पैक में बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, सरकार बताए कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चम्पावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि आबकारी नीति की यह धारा पर्यावरण को नुकसान करेगी। एक तरफ सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन को कार्यक्रम चला रही, दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है। सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं। सरकार ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि हर माह एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण को नुकसान होगा।

एक दिन में 13 हजार तीर्थयात्री ही कर सकेंगे बाबा के दर्शन, नई व्यवस्था के तहत बना यह प्लान

रुद्रप्रयाग। आनलाइन बुकिंग कराने वाले 13 हजार तीर्थयात्री ही केदारनाथ धाम में प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे। दो हजार का स्लाट आफलाइन बुकिंग कराने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए रखा गया है। नई व्यवस्था के अनुसार प्रति घंटे 1200 तीर्थ यात्रियों को ही बाबा के दर्शन कराए जाएंगे। बीते वर्ष तक दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। इससे वर्षा व बर्फबारी होने पर व्यवस्था गड़बड़ा जाती थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार टोकन व्यवस्था लागू की है। दर्शन के लिए प्रतिदिन 13 हजार तीर्थ यात्रियों की आनलाइन बुकिंग की जा रही है। आनलाइन पंजीकरण लेकर आए तीर्थ यात्रियों का सोनप्रयाग में क्यूआर कोड मशीन से सत्यापन होगा। इसके बाद ही उन्हें केदारनाथ जाने की अनुमति दी जाएगी। मंदिर में जाने से पहले तीर्थयात्री बेस कैंप के पास स्वर्गारोहणी कैंप स्थित स्लाट सिस्टम टोकन प्वाइंट पहुंचेंगे। यहां प्रति घंटे 1200 तीर्थ यात्रियों को टोकन दिया जाएगा। इसके बाद स्लाट पर्ची की मंदिर परिसर में लगी क्यूआर कोड स्कैन मशीन में जांच होगी और फिर तीर्थयात्री मंदिर में प्रवेश करेंगे। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि पर्यटन मित्र तीर्थ यात्रियों को दर्शन से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एक बार दर्शन करने के बाद संबंधित यात्री दोबारा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रत्येक यात्री को दर्शन के बाद अपनी स्लाट पर्ची ड्राप बाक्स में डालनी होगी।

अपमानजनक औरत शब्द को सम्पूर्ण भारत पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने को लेकर सिटी मैजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हल्द्वानी। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सदस्य प्रीति आर्या के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से अरबी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक औरत शब्द को सम्पूर्ण भारत पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर विद्यालयों के पाठ्यक्रम से औ से औरत शब्द हटाने के लिए संस्था पदाधिकारियों ने हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ज्ञापन भेजा।

इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू मार्गदर्शक पूजा लटवाल ने संयुक्त रूप से कहा की अरबी में औराह या औरत का मतलब महिला का गुप्तांग होता है फिर भी हमारे देश के विद्यालयों में बच्चों को बचपन से ही मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक औ से औरत शब्द की पढ़ाई कराई जा रही है जिससे हम अपने देश के होनहार बच्चों को बचपन से ही अरबी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित कर रहे है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है क्योंकि जब हमारे देश के होनहार बच्चों की शिक्षा ही अंधकार में चली जाएगी तो हमारे भारत देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा इसलिए हम भारत सरकार से यह माँग करते है कि अरबी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित औरत शब्द को सम्पूर्ण भारत में यथाशीघ्र प्रतिबंध कर विद्यालयों के पाठ्यक्रम से औ से औरत शब्द को हटाकर मातृशक्ति के सम्माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे मातृशक्ति की गरिमा में कोई ठेस ना पहुँचे क्योंकि वैदिक सनातन प्राचीन काल में प्रभु श्री राम जी ने माँ सीता जी के सम्मान में पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था और ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रोपदी जी के सम्मान में भागकर आए और चीर हरण के समय द्रौपदी जी के वस्त्र को बढ़ाकर उनकी रक्षा की और महाभारत करके सारे कौरवों को दण्ड दिलवाया क्योंकि वैदिक काल से ही सनातन में नारी को मातृशक्ति के रूप में पूजनीय माना गया है इसलिए हमें भी खुद को बदलना होगा क्योंकि जब हम बदलेंगे तब युग बदलेगा इसलिए हम सब मिलकर यह शपथ लें कि जब तक मातृशक्ति के सम्मान में अरबी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित औरत शब्द को पूर्ण रूप से सम्पूर्ण भारत देश में प्रतिबंध नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे क्योंकि भारत की नारी अपनी प्रतिभा को निखार कर भारत देश को प्रगति उन्नति की नई बुलंदियों में पहुँचाने और भारत देश को विश्व गुरु बनाने में अहम सहयोग दें रही है इसलिए भारत की मातृशक्ति का अपमान किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्राचीन काल से आज तक सनातन ने मातृशक्ति के मान सम्मान और विकास में प्रगति उन्नति लाने के लिए हमेशा ही दृढ़ता के साथ संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस दौरान ज्ञापन देने में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था संरक्षक हरीश चन्द्र पाण्डेय अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू उपाध्यक्ष लोकेश कुमार साहू सचिव नन्दकिशोर आर्या कोषाध्यक्ष बलराम हालदार समाजसेवी मनोज कुमार रवि गुप्ता मार्गदर्शक पूजा लटवाल प्रीती आर्या शौफाली जायसवाल चेतना लटवाल कंचन जोशी काजल खत्री जानकी रैगाई जानकी कश्यप नन्दकिशोर आर्या मुकेश साहू नवीन तिवारी संदीप यादव राजेश साहू रोहतास प्रजापति मुकेश बिष्ट अमन कुमार सुशील राय मुकेश कुमार सूरज कुम्हार आदि लोग उपस्थित रहे।

सैन्यधाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए : धामी

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैन्यधाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। सैन्य धाम का स्वरूप भव्य एवं दिव्य हो, इसके लिए अन्य राज्यों के सैन्य धामों (शौर्य स्थलों) की जो स्टडी की गई है, उनमें जो बेहतर कार्य किये गये हैं, उन कार्यों का समावेश सैन्य धाम में किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सैन्यधाम में उत्तराखण्ड की झलक दिखे। सैन्यधाम के आसपास केदारखण्ड एवं मानसखण्ड की थीम पर आधारित क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सचिवालय में सैन्य धाम (शौर्य स्थल) की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिये।

बैठक में जानकारी दी गई कि सैन्यधाम के निर्माण की कार्य प्रगति 45 प्रतिशत तक हो चुकी है। जिसके अन्तर्गत ऑडिटोरियम, टैंक प्लेटफॉर्म, मुख्य द्वार, बाबा जसवंत सिंह एवं बाबा हरभजन सिंह मन्दिर, शौर्य स्तम्भ, बुकिंग काउंटर, चाहरदीवारी एवं म्यूजियम का कार्य प्रगति पर है। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू, जी.ओ.सी उत्तराखण्ड सब-एरिया मेजर जनरल संजीव खत्री, मेजर जनरल सम्मी सभरवाल (से.नि) सचिव सैनिक कल्याण श्री दीपेन्द्र चौधरी, एस.एन. पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बालाकोट में वायु सेना ने तनाव के हालात में दिखाई अपनी ताकत : IAF प्रमुख वीआर चौधरी

नई दिल्ली। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने मंगलवार को 2019 में भारत के बालाकोट ऑपरेशन का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने दिखाया कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो 'नो वॉर, नो पीस' परिदृश्य में भी देश की वायुसेना की ताकत का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में वायु सेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी की थी। बता दें की वायु सेना प्रमुख एयरोस्पेस ताकत भविष्य की युद्ध क्षेत्र गतिविधियों की धुरी विषय पर मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह समृति सेमिनार में बोल रहे थे।

22 अप्रैल से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, पंजीकरण 15 लाख पार

ऋषिकेश। इस वर्ष भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 15 लाख से अधिक तीर्थ यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। सोमवार शाम तक 15 लाख 20 हजार 610 तीर्थ यात्री चारधाम आने के लिए अपना पंजीकरण करा चुके थे। सबसे अधिक उत्साह केदारनाथ की यात्रा के लिए देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए सबसे अधिक पांच लाख 40 हजार 286 तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। इसके बाद बदरीनाथ धाम के लिए साढ़े चार लाख, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए दो लाख 39 हजार और गंगोत्री धाम के लिए दो लाख 77 हजार तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया है।

चारधाम यात्रा पर एक नजर

- 22 अप्रैल को खोले जाएंगे गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट
- 25 अप्रैल को जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट
- 27 अप्रैल को खोले जाएंगे बदरीनाथ धाम के कपाट

यात्री पंजीकरण की स्थिति

- गंगोत्रीः 2,77,084
- यमुनोत्रीः 2,39,961
- केदारनाथः 5,40,286
- बदरीनाथः 4,56,128
- हेमकुंड साहिबः 7,141

केदारनाथ के लिए हेली बुकिंग

- 6263 यात्रियों की 25 से 30 अप्रैल तक हुई बुकिंग
- 09 हेलीपैड से आठ कंपनियों को मिली है उड़ान की अनुमति
- 7740 गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम का दोनों तरफ का किराया
- 5500 फाटा से केदारनाथ धाम का दोनों तरफ का किराया
- 5498 सिरसी से केदारनाथ धाम का दोनों तरफ का किराया

22 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा

बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए 21 फरवरी को, जबकि गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के लिए 16 मार्च को आनलाइन पंजीकरण खोले गए थे। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ऋषिकेश से यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 21 अप्रैल को रवाना होगा। चारधाम के अलावा हेमकुंड साहिब के लिए 7,141 तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया है।

चारधाम यात्रा के लिए शीघ्र ही ऋषिकेश में फोटोमैट्रिक पंजीकरण भी खोल दिया जाएगा। इसके लिए यात्रा ट्रांजिट कैंप में काउंटर तैयार हैं। चारधाम यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।

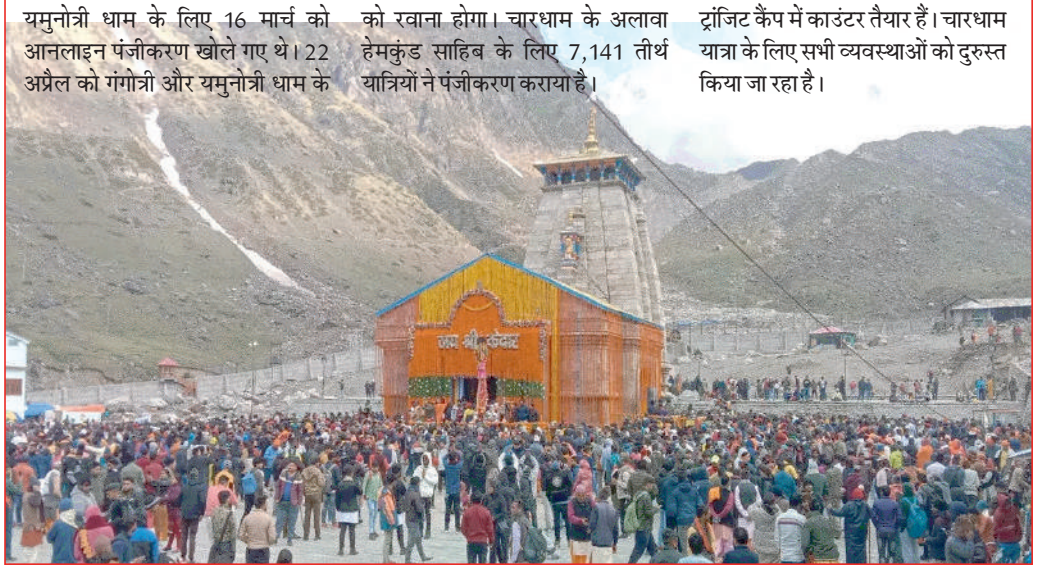

लोगों को मिलेगा ब्याजमुक्त ऋण

जयपुर में सहकारिता मंत्री बोले, डेढ़ लाख परिवार होंगे लाभान्वित

जयपुर, एजेंसियां। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1.50 लाख परिवारों को कृषि कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र आवेदक को 25 हजार से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारिता मंत्री सोमवार को सहकार भवन में राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए ऋण आवेदन पोर्टल का लोकार्पण कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोगों के लिए यह बजट घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गहलोत द्वारा जो घोषणा की गई उसे उसी वित्तीय वर्ष में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा जनता से जो वादे किये गये हैं विभाग उन्हें गति देकर क्रियान्वित की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि इस योजना में आरसीडीएफ को भी जोड़ा गया है ताकि डेयरी क्षेत्र में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन के कार्य कर रहे पशुपालकों को फायदा मिलेगा। सरकार का मकसद लाभ पहुंचाना है।

हुवावे का सस्ता स्मार्ट बैंड, पांच मिनट की चार्जिंग में चलेगा दो दिन

नई दिल्ली। हुवावे ने अपने नए फिटनेस ट्रैकर के तौर पर हुवावे बांड 8 को लांच कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह कंपनी का सबसे हल्का और सबसे पतला बड़े स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर है। कंपनी का दावा है कि इसे पांच मिनट चार्ज कर पूरे दो दिन तक यूज किया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें 1000 वॉच फेस का सपोर्ट मिलता है।

हुवावे बैंड-8 कंपनी का सबसे हल्का और सबसे पतला बड़े स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर है। केवल 14 ग्राम वजनी यह फिटनेस ट्रैकर 1.47-इंच एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन से लैस है और 368&194 पिक्सेल रिजॉल्यूशन और 65 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ एक 2.5डी हाई क्वालिटी वाली कर्व्ड ग्लास स्क्रीन प्रदान करती है। बैंड 8 फिटनेस ट्रैकर में चुनने के लिए 10,000 से अधिक वॉच फेस स्टाइल हैं। नया हुवावे बैंड 8 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि केवल पांच मिनट की चार्जिंग में इसे दो दिन यूज किया जा सकता है और फुल चार्ज होने में इसे 45 मिनट लगते हैं।

फुल चार्ज होने पर इसकी बैटरी 14 दिनों तक चल सकती है। हार्मनीओएस 3.1 के साथ आने वाला यह पहला हुवावे फिटनेस बैंड है। बैंड 8 हुवावे की ट्रूस्लीप 3.0 स्लीप मॉनिटरिंग तकनीक से लैस है। बेहतर एल्गोरिथ्म यूजर के लिए प्रोफेशनल और साइंटिफिक स्लीप एडवाइस प्रदान करता है। कंपनी ने चाइना स्लीप रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से स्मार्ट स्लीप इम्प्रूवमेंट प्लान भी लांच किया है, ताकि नींद की समस्या का सामना कर रहे यूजर्स के लिए सिस्टमैटिक और पर्सनलाइज्ड स्लीप इंटरप्रिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्लान्स की पेशकश की जा सके। कंपनी ने इसकी कीमत 3200 से 3600 रुपए तक रखी है।

2022 में कुल 149.5 लाख करोड़ रु मूल्य के 87 अरब 92 करोड़ भुगतान, यूपीआई सबसे लोकप्रिय

नयी दिल्ली,(वार्ता)। भुगतान सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वर्ल्डलाइन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनवरी दिसंबर 2022 के दौरान डिजिटल तरीकों से कुल 149.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 87 अरब 92 करोड़ से अधिक संख्या में लेन-देन किए गए। वर्ल्डलाइन की सोमवार को जारी इंडिया डिजिटल पेमेंट्स एनुअल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भुगतान के डिजिटल तरीकों में यूपीआई सबसे अधिक लोकप्रिय है और बेंगलुरु डिजिटल भुगतान के मामले में देश में अन्य जगहों से ऊपर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष डिजिटल लेन-देन की कुल संख्या यूपीआई से किए गए लेन-देन का हिस्सा 84 प्रतिशत रहा। संख्या की दृष्टि से कुल लेन-देन में व्यक्तियों द्वारा दुकानों को (पी2एम) किया गया भुगतान का 40 प्रतिशत और व्यक्तियों के बीच (पी2पी) के लेन-देन 44 प्रतिशत रहा। कुल डिजिटल भुगतान में मूल्य के हिसाब से भी यूपीआई की हिस्सेदारी 84 प्रतिशत रही। पी2एम का हिस्सा 18 फीसदी और पी2पी का हिस्सा 66 प्रतिशत रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी कुछ पी2पी के इन आंकड़ों में भुगतान के अलावा व्यक्तियों के बीच धन के हस्तांतरण के लेन-देन है, शामिल हो सकते हैं। यूपीआई के बाद दूसरा स्थान क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान का आता है। वर्ष के दौरान संख्या के हिसाब से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से किया गया भुगतान सात प्रतिशत रहा, जबकि भुगतान के मूल्य के हिसाब से इनका हिस्सा 14 प्रतिशत था।

मारुति सुजुकी ने लांच की नई सुपर कैरी मिनी ट्रक

नई दिल्ली। यात्री वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने हल्के वाणिज्यिक वाहन सुपर कैरी का उन्नत संस्करण पेश करने की आज घोषणा की। कंपनी ने कहा कि बेहतर गुणवत्ता और प्रदर्शन को महत्व देने वालों के लिए निर्मित, सुपर कैरी अब मारुति सुजुकी के 1.2 लीटर के-सीरीज डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन से द्वारा संचालित है। मारुति सुजुकी का सुपर कैरी मिनी-ट्रक 4-सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित है। नए इंजन को उन्नत फाइव-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है जो बेहतर ग्रेडेबिलिटी प्रदान करता है जिससे ग्राहकों को पहले की तुलना में अधिक बेहतर ग्रेडिएंट ड्राइव का अनुभव मिलता है। नई सुपर कैरी के लांच के साथ मारुति सुजुकी ने एक नया सीएनजी कैब चेसिस वेरिएंट भी पेश किया है। ये मिनी ट्रक सीएनजी डेक, गैसोलाइन डेक और गैसोलाइन कैब चेसिस वेरिएंट में उपलब्ध है। नई सुपर कैरी फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ एक नए इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम से सुसज्जित है। बेहतर गतिशीलता को सक्षम बनाने के लिए हल्के संचालन के साथ एक बड़ा स्टीयरिंग व्हील ड्राइविंग को आरामदायक बनाता है।

थोक महंगाई दर 29 महीने में सबसे कम

नई दिल्ली। थोक महंगाई दर मार्च में घटकर 1.34 प्रतिशत पर आ गई है। यह 29 महीने का निचला स्तर है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85 प्रतिशत रही थी। जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 4.73 प्रतिशत थी। गेहूं, दालें और फ्यूल जैसी चीजों के सस्ते होने से महंगाई में ये गिरावट आई है। अक्टूबर 2020 में यह 1.31 प्रतिशत पर थी। ये लगातार 10वां महीना है जब होल सेल महंगाई गिरी है। पिछले सोमवार को रिटेल महंगाई के आंकड़े भी जारी किए गए थे। मार्च 2023 में यह घटकर 5.66 प्रतिशत पर आ गई है। खान-पीने के सामान के दामों में गिरावट आने से रिटेल महंगाई घटी थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की होती है। मार्च में थोक महंगाई दर में गिरावट खान-पीने के सामान, टेक्सटाइल्स, मिनरल्स, रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट की कीमतों में गिरावट के चलते आई है।

वहीं क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने से भी महंगाई घटी हैं। फरवरी में खाने के सामान की थोक महंगाई दर 2.76 प्रतिशत थी, ये मार्च 2.32 प्रतिशत पर आ गई। मार्च में रोजाना जरूरत के सामानों की महंगाई 3.28 प्रतिशत से घटकर 2.40 पर आ गई। ईंधन और बिजली की थोक महंगाई फरवरी के 14.82 प्रतिशत से गिरकर 8.96 प्रतिशत पर आ गई। मेन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई भी 1.94 प्रतिशत से गिरकर निगेटिव जोन में चली गई। मार्च में गेहूं की थोक महंगाई दर 9.16 प्रतिशत रही है।

IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु पर भारी पड़े सुपर किंग्स, चेन्नई ने 8 रन से जीत लिया मैच

बंगलुरु। इंडियन प्रीमियर लीग का 24वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स व रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच खेला गया, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 रन से जीत लिया। बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 226 रन बनाए। फिर चेन्नई ने 227 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को 20 ओवर में 218/8 रन पर रोक मैच अपने नाम कर लिया। इससे पहले चेन्नई के लिए ओपनर डेवोन कॉन्वे (45 गेंदों पर 83 रन) और शिवम दुबे (27 गेंदों पर 52 रन) तूफानी अद्र्धशतक जमाए। इन दोनों के अलावा, अजिंक्या रहाणे ने 20 गेंदों पर 37 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ तीन रन ही बना सके। बंगलुरु की ओर से वेन पार्नेल, विजयकुमार वैशाक, मोहम्मद सिराज, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल और ग्लेन मैक्सवेल को एक-एक विकेट मिला। चेन्नई के लिए नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे शिवम दुबे ने 25 गेंद पर फिफ्टी पूरी की। यह उनकी इस सीजन की पहली और ओवरऑल चौथी आईपीएल फिफ्टी है। इस पारी में दुबे ने पांच छक्के और दा चौके लगाए। इसके साथ ही उन्होंने डेवोन कॉन्वे के साथ 80 रन की पार्टनरशिप भी की। चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर डेवोन कॉन्वे ने शुरुआती विकेट गिरने के बाद भी एक एंड संभाले रखा। उन्होंने 45 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली। उन्होने 184.44 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। कॉन्वे की पारी में छह चौके और छह छक्के शामिल रहे। कॉन्वे ने इस सीजन में अपना दूसरा और करियर का 5वां आईपीएल अद्र्धशतक जड़ा।

खेल का रिस्पेक्ट करोगे, तो खेल भी आपसे प्यार करेगा, अर्जुन के डेब्यू पर सचिन तेंदुलकर का इमोशनल पोस्ट

मुंबई। दो साल आईपीएल के डगआउट में बैठने के बाद सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को रविवार को कोलकाता के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस से डेब्यू करने का मौका मिला।

अर्जुन 2021 से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े थे, लेकिन अब तक उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला था। बेटे के डेब्यू के बाद मास्टर ब्लास्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए खेल के प्रति सम्मान और जुनून को बरकरार रखने की सलाह दी। सचिन ने पोस्ट में कहा, आपके पिता होने के नाते, जो कि आपको प्यार करता है और खेल के प्रति जुनूनी है, मैं जानता हूं कि आप खेल को सम्मान देना जारी रखोगे, जिसका वह हकदार है और खेल वापस आप पर प्यार लुटाएगा। आप अगर खेल को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको खेल भी प्यार करेगा और आपके सम्मान को भी वापस लौटाएगा। उन्होंने कहा कि आपने यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है और मुझे यकीन है कि ऐसा करना जारी रखेंगे।

अतंरराष्ट्रीय

जी7 के विदेश मंत्रियों ने ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली का किया स्वागत

तोक्यो, (वार्ता)। जी7 देशों के शीर्ष राजनयिकों ने मंगलवार को ईरान और सऊदी अरब द्वारा आपसी संबंधों को सुधारने की पहल का स्वागत किया।

जी7 के विदेश मंत्रियों ने जापान के करुइजावा में अपनी बैठक के बाद जारी एक सामूहिक बयान में कहा, "हम देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और क्षेत्र में तनाव कम करने की पहल का स्वागत करते हैं, जिसमें ईरान और सऊदी अरब के हालिया समझौते शामिल हैं।" गौरतलब है कि ईरान और सऊदी अरब मार्च में चीन की मध्यस्थता के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। दोनों देशों के संबंध 2016 में शिया उपदेशक निम्र अल-निम्र की हत्या के बाद ईरान में सऊदी अरब के राजनयिक मिशनों पर हमला किये जाने के बाद टूट गये थे।

अमरीका में चीन ने बना रखा था खुफिया थाना, जानकारी जुटाकर भेज रहे थे देश, दो गिरफ्तार

वाशिंगटन। अमरीका के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क शहर में दो चीनी मूल के अमरीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि ये लोग खुफिया पुलिस थाना चलाकर चीन को जानकारी पहुंचा रहे थे। अमरीका के न्याय विभाग ने बताया कि चीनी मूल के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने 2022 की शुरुआत में मैनहट्टन के चाइनाटाउन में खुफिया पुलिस चौकी खोली थी। विभाग ने चीन के राष्ट्रीय पुलिस बल के 30 से अधिक अधिकारियों पर कथित तौर पर अमरीका में असंतुष्टों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। न्यूयार्क के पूर्वी जिले के अटार्नी ब्रियोन पीस ने यह जानकारी दी है।

अटार्नी पीस ने कहा कि दो अधिकारियों को सोमवार सुबह मैनहट्टन में एक अज्ञात कार्यालय भवन में कथित रूप से चीनी राष्ट्रीय पुलिस का एक खुफिया थाना स्थापित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों प्रतिवादियों को जब एफबीआई जांच के बारे में पता चला तो उन्होंने चीनी राष्ट्रीय पुलिस के साथ अपने संचार के सबूतों को नष्ट कर दिया। एक दूसरी शिकायत में 34 अधिकारियों पर एक टास्क फोर्स का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है जो इंटरनेट ट्रोल फ़र्म के रूप में काम कर रही है और हज़ारों फर्जी ऑनलाइन व्यक्तियों को जोड़ रही थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अमेरिका सहित दुनिया भर में असंतुष्टों और कार्यकर्ताओं को परेशान करने और धमकाने के लिए किया।

पीस ने कहा टास्क फोर्स ने कथित तौर पर अमेरिकी लोकतंत्र और विदेश नीति की कमजोरियों को रेखांकित करने वाली गलत जानकारी फैलाने के लिए अपनी फर्जी ऑनलाइन आईडी का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों को जब पता चला कि इनकी जांच की जा रही है तो इन्होंने चीन के सार्वजनिक मंत्रालय से हुई बातचीत की जानकारी को हटा दिया। यह लोग अमरीका में रह रहे चीन के लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, जो अमरीकी कानूनों का उल्लंघन है। एक अलग प्रेस विज्ञप्ति में न्याय विभाग ने कहा कि तीसरी शिकायत में दस लोगों पर आरोप लगाया गया है, जिनमें छह एमपीएस अधिकारी और चीन के साइबरस्पेस प्रशासन के दो अधिकारी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रतिवादियों में से नौ चीन में रहते हैं और फरार चल रहे हैं। इसके अलावा दसवां प्रतिवादी इंडोनेशिया या चीन में रहता है और वह भी फरार चल रहा है।

छोटी खबरें

अनुराग-प्रवेश वर्मा कीहेट स्पीचः एफआईआर दर्ज करने की मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब

नई दिल्ली। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीपीएम नेता बृंदा करात की याचिका में 2020 में सीएए विरोधी आंदोलन के खिलाफ दोनों सांसदों के भडक़ाऊ बयानों का हवाला दिया गया है। इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुके हैं। जस्टिस जोसेफ ने अनुराग ठाकुर की 'गोली मारो' वाली टिप्पणी पर भी ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरा मानना है कि गद्दार का मतलब देशद्रोही होता है? यहां पर गोली मारो दवाई से संबंधित निश्चित रूप से नहीं था।

दक्षिण हिंद महासागर में बदले 19 जगहों के नाम, चीनी मीडिया ने कहा

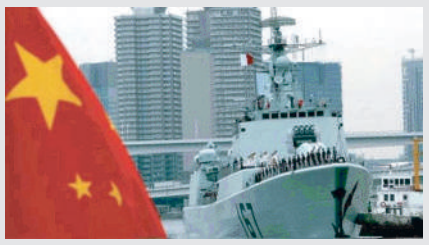

बीजिंग। चीन के विस्तारवादी रवैये का पूरी दुनिया विरोध करती है। शातिर और चालबाज चीन ने पहले चुपके से अरुणाचल प्रदेश के गांवों के नाम बदल दिए थे, जिसकी भारत ने निंदा की थी। अब दक्षिणी हिंद महासागर में 19 स्थानों के नाम बदले हैं। चीन की तरफ से दक्षिण हिंद महासागर में 19 तलों के नाम बदलने की हिमाकत की गई है। चीन की ओर से की गई यह कार्रवाई भारत कीसंप्रभुता और हिंद महासागर के इलाके में भारतीय प्रभाव पर सीधा दखल है। एक महीने के भीतर शी जिनपिंग की भारत की संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ की यह दूसरी हिमाकत है। इसे चीन के विस्तारवादी रवैये और हिंद क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखल के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले दो फरवरी को चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदल दिए थे। इसकी भारत ने कड़ी निंदा की थी और चीनी दावों को सिरे से नकार दिया था। चीन के दक्षिण हिंद महासागर में जिन 19 जगहों के नाम बदलने की बात सामने आई है, वे भारतीय प्रायद्वीप से करीब 2000 किलोमीटर दूर हैं। चीनी मीडिया ने इसे बीजिंग का 'सॉफ्ट पॉव्र' प्रोजेक्शन कहा है। बता दें कि 2011 में इंटरनेशनल सी बेड एथॉरिटी ने चाइना ओशियन मिनरल रिसोर्सेस आरएंडडी एसोसिएशन यानी सीओएमआरए के साथ मेडागास्कर के पास हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम रि में 15 साल के लिए एक उत्खनन अनुबंध किया थ, जो चीन की मुख्य भूमि से दूर था।

वीकेसी ग्रुप को मिला आईपीयूए पुरस्कार

नयी दिल्ली (वार्ता)। अग्रणी पीयू फुटवियर निर्माता वीकेसी ग्रुप ने एक नया बाजार बनाने और चप्पलों और सैंडल में पॉलीयुरेथेन (पीयू) फुटवियर को लोकप्रिय बनाने में योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंडियन पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन (आईपीयूए) अवार्ड जीता था। वीकेसी ग्रुप डायरेक्टर वीपी अज़ीज़ ने नोएडा में आयोजित पीयू टेक 2023 समारोह में मिलिकेन इंडिया के कारोबार प्रमुख आलोक तिवारी से पुरस्कार प्राप्त किया।

सुप्रीम कोर्ट सवारी का साधन नहीं; महाराष्ट्र सरकार को फटकार, मुंबई मेट्रो पर दस लाख रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली। मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने यह तक कह दिया कि आपने (महाराष्ट्र सरकार) सुप्रीम कोर्ट को सवारी का साधन मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के चलते महाराष्ट्र सरकार पर नाराजगी जाहिर की। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अधिक पेड़ काटने की मांग के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दो हफ्ते के भीतर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब 84 पेड़ काटने की इजाजत दे दी गई, तो आप (महाराष्ट्र सरकार) 185 पेड़ काटने की नीयत के साथ वृक्ष प्राधिकरण के पास चले गए। इस काम को करने के बाद मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एमएमआरसी) ने कोर्ट की अवमानना की है। अब अथॉरिटी को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। उनका ये तौर तरीका ठीक नहीं है। नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आपको जब जरूरत हुई, हमने इजाजत दी, लेकिन आप और ज्यादा पेड़ काटने के लिए सीधे वृक्ष प्राधिकरण के पास चले गए। कोर्ट का रुख देखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना शर्त उस कदम के लिए माफी मांग ली और हलफनामा दाखिल करने की बात भी कही।

समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन पर छेड़खानी और लूट का मुकदमा दर्ज

प्रताप गढ़ (वार्ता)। उत्तर प्रदेश में प्रताप गढ़ जिले के समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पर आज महिला के साथ छेड़खानी और लूट का मुकदमा दर्ज हुआ।

पुलिस ने बताया कि पीडित महिला काजल पत्नी राजेन्द्र की शिकायत पर कुन्डा कोतवाली में गुलशन यादव के खिलाफ छेड़खानी और लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है।

गुलशन यादव कुंडा नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सीमा यादव के पति है। गुलशन पर महिला ने घर में घुसकर मारपीट, लूट, छेड़खानी करने कपड़ा फाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाये हैं।

पुलिस के अनुसार, महिला की तहरीर पर कुन्डा कोतवाली में गुलशन यादव सहित 5 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज होने से पंचायत चुनाव का माहौल गरमा गया है।

कुशल भारतीय आबादी से पूरी दुनिया को फायदा हो सकता हैः बिरला

नयी दिल्ली (वार्ता)। आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) संसदीय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने नॉर्वे की सांसद सुश्री ट्राइन लिज़ सुंडनेस के नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में मंगलवार को मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए श्री बिरला ने उम्मीद जताई कि यह यात्रा भारत और ईएफटीए देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भारत और ईएफटीए देश विश्व शांति, अहिंसा, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता साझा करते हैं जो एक 'जीवंत लोकतंत्र' का आधार है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हाल के वर्षों में भारत और ईएफटीए देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सम्बन्धो को और अधिक गति देने के लोगों से लोगों का संपर्क को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पिछले साल कोपेनहेगन में आयोजित दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान आइसलैंड और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि इस यात्रा ने द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को गति दी है।

घाटी में विदेशी आतंकवादियों की भरमार, रिपोर्ट में दावा, जम्मू-कश्मीर के युवा छोड़ रहे मिलिटेंसी

श्रीनगर, एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की संखिया स्थानीय चरमपंथियों से ज्यादा है। इसका खुलासा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाल ही में गृह मंत्रालय की एक मीटिंग किया गया। इसका मतलब है कि कश्मीरी युवा अब इस मिलिटेंसी से दूर जा रहे हैं। यही वजह है कि विदेशी मिलिटेंटों की संख्या यहां ज्यादा है। बीते वर्षों में इस ट्रेंड में काफी बदलाव हुआ है। इस सुरक्षा समीक्षा बैठक में सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में कुल 137 मिलिटेंट ही बचे हुए हैं और इन में विदेशी मिलिटेंटों की संख्या 90 हैं, जबकि स्थानीय 47 हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साझा की गई इस विदेशी मिलिटेंट्स की संख्या में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैबा शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा समीक्षा बैठक में सुरक्षा एजेंसियों ने इन विदेशी मिलिटेंट्स के सुरक्षा चक्र से मुठभेड़ के दौरान भागने में नई रणनीति का खुलासा किया है, जिसकी मदद से यह सुरक्षा बलों के तकनीकी सर्विलांस से भी बच निकलते हैं। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में हाल ही में ऐसी दो मुठभेड़ हुई, जिनमें मिलिटेंटों के साथ संपर्क होने के बाद भी मिलिटेंट मुठभेड़ स्थल से फरार होने में सफल रहे। गृह मंत्रालय में सूत्रों के अनुसार सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यह बात स्पष्ट की गई हैं कि स्थानीय युवा मिलिटेंसी में शामिल नहीं हो रहे हैं। यह मिलिटेंट संगठनों के लिए चिंता और चुनौती हैं जिसके लिए उन्होंने रणनीति में बदलाव किया है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पर प्रहार करने में ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ-साथ मोबाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल रहा है, जिसके कारण आज जम्मू-कश्मीर में स्थानीय मिलिटेंटों की संख्या रिकॉर्ड कम हैं।

नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान कई लोग अलग-अलग जिले से अपनी समस्या लेकर सीएम के पास आए. सीएम ने लोगों की समस्या सुनने के बाद तुरंत ही समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिया.इस बीच सुपौल जिले से बियाडा में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपनी समस्या बताई. उसने कहा कि 2003 तक वह अनुकंपा पर बहाल था, लेकिन 2007 नियमावली के आधार पर उसे हटा दिया गया. इसके बाद सीएम ने कहा जरा उद्योग विभाग को फोन लगाओ. अधिकारी को फोन लगा कर कहा कि आपके बियाडा में है. अगर किसी पिता की मृत्यु हो गई है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप? कुछ कीजिए, और इस बारे में हमें बताएं कि क्या किया.

फोन रखने के बाद सीएम ने एक अधिकारी को बुलाकर कहा इधर आइए. फिर उनसे पूछा कि बियाडा में ऐसा नहीं है क्या? अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो घर के किसी को सहयोग दिया जाए. फिर सीएम ने कहा अरे भाई इसमें भी कर देना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में तो ऐसा करते ही हैं, तो इसमें में भी देख लेना चाहिए. सीएम ने कहा कि कॉर्पोरेशन कौन सरकार ही न बनती है, तो इसमें भी यह सेवा होनी चाहिए. फिर सीएम ने कहा कि अगर किसी के पिता की मौत हो गई है तो क्या कर सकते हैं. ये सब बताइएगा. इस तरह कई और लोगों ने सीएम से अपनी समस्या बताई। बता दें कि अप्रैल माह के तीसरे सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास, खाद उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, योजना विकास, भवन निर्माण, पर्यटन, सूचना एवं जनसंपर्क, वाणिज्य तथा सामान्य प्रशासन विभाग की शिकायत सुनने के बाद समस्याओं के निपटारे के आदेश भी दिए।

कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। राज्य में कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना के संबध में निर्णय। नाबार्ड की आर0आई0डी०एफ० योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु रू0 304 करोड़ स्वीकृत किये गये है, जिसमें कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 01 लाख कृषकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार के साधन प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आयेगी एवं सब्जियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

भारत सरकार द्वारा निर्गत तिब्बतन पुनर्वास नीति-2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मौजा तरला नांगल, देहरादून में फैले हुए गरीब तिब्बतन शरणार्थीयों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवासीय योजना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गयी है। मौजा तरला नांगल स्थित उक्त भूमि पर गरीब तिब्बतन शरणार्थियों के लिए प्रस्तावित आवासीय योजना में शमन मानचित्र संख्या- एसआर-0277/ 20.21 मैजर नोरबू संयुक्त सचिव एफडेबल हाउसिंग फार तिब्बतन रिफ्यूजी रिहैबीटेसन में विद्यमान निर्माण की प्रशमन / स्वीकृति के क्रम में आंकलित धनराशि रूपये 65,71,068.00 में छूट प्रदान किये जाने का निर्णय।

ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।

निदेशालय विभागीय लेखा के अन्तर्गत वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंह नगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों में सहायक लेखाकार का पद सृजित न होने के कारण उक्त कार्यालयों में शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पन्न किये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु विभागीय लेखा में लेखाकार के कुल 21 सृजित पदों में निदेशालय एवं कैम्प कार्यालय के लिये सृजित 08 रिक्त पदों में से 04 रिक्त पदों को डाउनग्रेड कर सहायक लेखाकार के पदों में परिवर्तित करते हुए वित्तीय

परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंहनगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत हेतु क्रमशः एक-एक पद आवंटित किये जाने का निर्णय।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के ढाँचे में अस्थाई (निःसंवर्गीय) 30 पदों के सृजन का निर्णय।

राज्य की बंद पड़ी चीनी मिल गदरपुर की भूमि को सर्किल रेट अथवा बाजार मूल्य पर विक्रय किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिमण्डल की दिनांक 27 जुलाई 2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 17 अगस्त 2022 एवं दिनांक 23 मार्च 2023 को सम्पन्न बैठक में हुये विचार विमर्शोपरान्त गदरपुर चीनी मिल की भूमि को कय किये जाने हेतु सिडकुल / औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सिडकुल को विक्रय कर लिया जाए तथा गदरपुर चीनी मिल की भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि का सिडकुल द्वारा बैंक खाता खोला जाय तथा सिडकुल के ऑफर प्रपोजल से अधिक धनराशि प्राप्त होने पर प्राप्त अधिक धनराशि को राज्य सरकार / गदरपुर चीनी मिल के कस्टोडियन उत्तराखण्ड शुगर्स को वापस किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

जनपदों में कई बार जिला योजना समिति की बैठकों में निर्धारित गणपूर्ति (1/2 सदस्य उपस्थित) न होने के कारण जिला योजना समिति की बैठकें बार बार स्थगित होने के फलस्वरूप विकास सम्बन्धी कार्यों में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में लागू उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के नियम 29 (गणपूर्ति) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की संख्या 1/2 के स्थान पर 1/3 सदस्यों तथा प्रथम बार गणपूर्ति न होने की दशा में स्थगित बैठक के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) नियमावली 2023 प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग तथा समस्त स्थानीय निकाय चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। इस चिन्हित क्षेत्र से बाहर, एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर तक हो तथा अधिकतम ऊंचाई 9.00 मीटर तक हो तथा समस्त गैर एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर तक एवं ऊंचाई 6.00 मीटर तक हो, मानचित्र स्वीकृत स्वप्रमाणन / शपथ पत्र के द्वारा किये जायेंगे। एम०डी०आर०/ ओ०डी०आर० मार्ग, चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों ओर पर्वतीय क्षेत्रों मे 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले शुल्क यथा उप विभाजन शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क इत्यादि पर वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत शोध अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदों का विभागीय संरचनात्मक ढांचे में निर्धारण किये जाने की स्वीकृति।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 12.11.2021 को पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत नगर पंचायत सिरौंलीकलां के गठन सम्बन्धी अधिसूचना को वापस लिये जाने का निर्णय।

कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में बैंकों के साथ ऐसे लेखपत्र जिनका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य नहीं था, को डिजिटल / विधिक रूप में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त ई-स्टाम्प सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। उक्त संशोधन के उपरांत बैंक एवं आम जनता को निम्न सुविधायें प्राप्त होगी- हितधारकों को बैंक ऋण, बैंक गारण्टी, बन्धक इत्यादि के लिये स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प कय नहीं करना पड़ेगा। उक्त डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली से बैंक सम्बन्धी कार्यवाही बैंक के पटल पर ही सम्पादित हो जायेगी। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के माध्यम से स्टाम्प कय की सुविधा बैंक को अपने ही परिसर में उपलब्ध होगी। उक्त प्रणाली के प्रवृत्त होने के पूर्व बैंक ऋण इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले स्टाम्प का विवरण विभाग को उपलब्ध नहीं होता था। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के पश्चात्बैंक में प्रयुक्त होने वाले अभिलेख यथाविधि स्टाम्पिंग होंगे, जिससे विभाग की आय में भी वृद्धि होगी एवं स्टाम्प का लेखा उचित तरीके से संकलित होगा। उक्त प्रक्रिया के सरलीकरण के फलस्वरूप जनहित में EODB प्रणाली को बल मिलेगा।

आपदा के कारण कार्य की संवेदनशीलता, तात्कालिकता एवं जिलाधिकारी चमोली द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-1084/2021 के अन्तर्गत 'जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हल्दापानी लॉ कॉलेज के निकट भू-धंसाव एवं भूस्खलन की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक कार्य' की प्रथम बार निविदा में सफल एकल निविदादाता के साथ अनुबन्ध गठित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया था। मंत्रिमण्डल द्वारा इसका अनुमोदन दिया गया है।

उत्तराखण्ड में आधारभूत ढांचागत अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board UIIDB गठन के संबंध में उत्तराखण्ड निवेश और आधारित संरचना (विकास एवं विनियम) अध्यादेश, 2023 को मंजूरी।

उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को दिये जाने वाले त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ते को प्रतिमाह भुगतान किये जाने का निर्णय।

राज्य में संचालित जी०एस०टी० ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना 'बिल लाओ ईनाम पाओ' का एक साल के लिए विस्तार दिये जाने की स्वीकृति।

उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा पर वर्तमान में 20 प्रतिशत की दर से वैट कर वसूल किये जाने की व्यवस्था है जो कि राज्य के सीमावर्ती राज्यो में प्रचलित दरों से अधिक है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा का मूल्य सीमावर्ती राज्यो से अधिक होता है। जिससे राज्य में अवैध मदिरा की बिक्री होने की सम्भावना बनी रहती है। जिससे राज्य की राजस्व प्राप्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023-24 निर्गत की गयी है। जिसके प्रस्तर 12.1 में विदेशी मदिरा के मूल्य को कम करते हुए निर्धारण किये जाने हेतु सूत्र का उल्लेख किया गया है। जिसमें विभिन्न घटको के साथ ही राज्य में विदेशी मदिरा पर लगने वाले वाणिज्य कर की दर 12 प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। उक्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति, 2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से राज्य में लागू की गयी है। इस व्यवस्था को भी दी गई मंजूरी।

प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for excellence) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 05 की.मी. की परिधि में राज्य के 603 प्राथमिक तथा 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों मे रूप में विकसित एवं सुविधा सम्पन्न बनाये जाने पर दी गई सहमति।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना में निर्णय लिया गया कि अब नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित होम स्टे योजना सब्सिडी नही दिये जाने पर सहमति। ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों हेतु योजना पूर्ववत रहेगी।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 06 इंजीनियरिंग संस्थानों कमशः प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ एवं टी. एच. डी.सी. - आई.एच.ई.टी. नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कालेज, उत्तरकाशी को As is where is basis के आधार पर वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के अधीन कैम्पस कालेज के रुप में संचालित किये जाने की कतिपय शर्तो के अधीन मा० मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त के फलस्वरुप सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों में बी. ओ.जी. यथावत कार्य करती रहेगी।

नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ का संचालन वायुसेना द्वारा लिये जाने का निर्णय। जब तक वायुसेना द्वारा इसका विधिवत संचालन नही किया जाता तब तक इसके संचालन हेतु एयर पोर्ट अथॉरिटी से एम.ओ.यू. किये जाने की स्वीकृति। गैरसैण में आयोजित हुये विधान सभा सत्र के सत्रावसान का कैबिनेट द्वारा किया गया औपचारिक अनुमोदन।

फिर वायरल हुआ शिवम सडाना का गाना दारु सी, गाने को मिले 1 crore व्यूज

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। भारतीय रैपर एवं गायक शिवम्सडाना के गाने ने रिलीज़ होते ही तेहेलका मचा दिया/ रिलीज़ होने के कुछ ही दिनों में गाने को 1 crore लोगों ने देखा और गाना वायरल हो गया / यही नहीं इस गाने को इस बार १ लाख लोगों ने लाइक यनि पसंद किया है/ इस गाने को लिखा और कंपोज़ सडाना ने ही किया है/ इस गाने को शिवम्के खुद के इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल ₹शिवम्सडाना₹ में ही मुंबई से रिलीज़ किया गया है/ इस गाने की म्यूजिक प्रोडक्शन मनदीप सिंह और डायरेक्शन रोहित कुमार ने की है/ इस गाने मे पंजाब की ख़ूबसूरत मॉडल एवं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कौर नव ने अभिनय किया है/ इस गाने में सडाना लाल हेलीकाप्टर के साथ खड़े हुए अभिनय करते नज़र आ रहे हैं / शिवम सडाना ने संजीत के क्षेत्र में पंजाबी समाज का नाम पूरे भारत में बढ़ाया है। सडाना बताते हैं की इस यह एक पार्टी सांग है जो की युवाओं को बहुत पसंद आएगा/ इस गाने में लड़की की ख़ूबसूरती को दारू के नशे से तुलना दी गई है/ में समाज में बढ़ते नशे के खिलाफ हूँ / सडाना ने अपने इस गाने के आखिर में बहुत ही अच्छा स्लोगन भी दिया है ₹दारु पीना हमारे स्वास्थ और प्यार दोनों ही के लिए हानिकारक है 'शिवम सडाना ने इस 14 फेब valentines day को अपना खुद का लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट भी किया जो की रायवाला ऋषिकेश रोड में स्थित' the midway रिसॉर्ट्स' में हुआ /

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक/संपादक- विकास गर्ग ने भगवती प्रिंटिंग प्रेस, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार उत्तराखंड से मुद्रित करवाकर 54 आवास विकास, विवेक विहार, रानीपुर मोड़, हरिद्वार उत्तराखंड से प्रकाशित किया।
प्रकाशक / संपादक : विकास गर्ग- फोन : 9897766448, : मुख्य संपादक / सुमित तिवारी- फोन : 8077771906 : Email : uttarakhandprahari19@Gmail.com